

प्रति,

आर०टी०पालीवाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानियन्त्रक,
मो० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 2

देहरादून : दिनांक : 24 अगस्त, 2007

विषय: जिला उत्तरकाशी में न्याय विभाग के अधिकारियों के लिए आवासीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2007-2008 में अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 673/यू०एच०सी०/एडमिन(बी)/निर्माण/2006, दिनांक 1.3.2007 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस सन्बन्ध में शासनादेश संख्या-5-दो(1)/XXXVI(1)/2006, दिनांक 9.6.2006 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला उत्तरकाशी में न्याय विभाग के अधिकारियों के लिए आवासीय भवनों के निर्माण हेतु पूर्व अनुमोदित लागत रुपये 47,66,000/- के सापेक्ष पुनरोक्षित रु० 50,12,000/- (पचास लाख बारह हजार रुपये मात्र) की लागत पर प्रस्तावकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2007-08 में पुनरोक्षित लागत के विरुद्ध अवशेष अतिरिक्त धनराशि रु० 2,46,000/- (दो लाख छियालीस हजार रुपये मात्र) को व्यय किये जाने की महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) आगमन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें सिट्यूट ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से लो गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा । तदोपरान्त ही आगमन की स्वीकृति मान्य होगी ।
- (2) इस धनराशि के पूर्ण उत्पन्न के सम्बन्ध में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति बताते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रत्येक माह उपलब्ध कराया जाय ।
- (3) कार्य एक निश्चित समयावधि में समाप्त हो, इसके लिए निर्माण इकाई समयान्तर्गत पूरे कार्य का टेण्डर प्रकाशित करते हुए टेकेंदार से हुए अनुबन्ध की प्रति शासन में उपलब्ध कराये ।
- (4) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगमन एवं गानाचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय, तदोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।
- (5) कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में लागत के पुनरोक्षण के लिए शासन द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी ।
- (6) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगमन गठित कर निबन्धानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाय ।
- (7) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित किया जाय ।

- (8) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भूतल-भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य कर ली जाय । निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय ।
- (9) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।
- (10) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पाये जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय ।
- (11) निर्माण कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या 2047/XIV/219(2006), 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।
- (12) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, भित्तव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेंसी/अभिशासी अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे ।
- (13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2008 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा-शीर्षक "4059-लोकनिर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-60 अन्य भवन-051- निर्माण-00-आयोजनागत-03-न्यायिक कार्यों हेतु भवनों का निर्माण-24-बृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-799/XXVII(5)/2007, दिनांक 21.8.07 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)
सचिव ।

संख्या-22-दो(8)/XXXVI(1)(2)/2007-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. जिला न्यायाधीश, उत्तरकाशी ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/उत्तरकाशी ।
5. मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी ।
7. नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन ।
8. एन०आई०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।